



अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ मुलाकात पर पीएम मोदी ने कहा-सार्थक संवाद हुआ

नई दिल्ली ३१/१२ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ हुई मुलाकात पर कहा है कि संवाद सार्थक रहा है। 'आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन' विकसित भारत का एजेंडा' विषय पर यह मुलाकात मंगलवार को हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ एक बहुत सार्थक संवाद हुआ। उन्होंने 'आत्मनिर्भरता और संरचनात्मक परिवर्तन' विकसित भारत के लिए कार्यसूची' विषय पर अपने बहुमूल्य दृष्टिकोण साझा किए। बता दें कि मंगलवार सुबह नीति आयोग में पीएम मोदी ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के एक ग्रुप के साथ बातचीत की। इस दौरान, प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित



करते हुए साल 2047 तक भारत की यात्रा के मूल स्तंभों का उल्लेख किया। उन्होंने 'विकसित भारत' को एक राष्ट्रीय आकांक्षा बताते हुए कहा कि साल 2047 तक एक विकसित भारत का सपना सरकारी नीति से परे जाकर एक वास्तविक जन आकांक्षा बन गया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव शिक्षा, उपभोग और वैश्विक गतिशीलता के बदलते स्वरूपों में स्पष्ट है, जिसके लिए तेजी

से महत्वाकांक्षी होते समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थागत क्षमता में वृद्धि और सक्रिय अवसंरचना नियोजन की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने वैश्विक क्षमता निर्माण और वैश्विक एकीकरण प्राप्त करने के लिए मिशन-आधारित सुधारों की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन-आधारित सुधारों का आह्वान किया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की नीति निर्माण और बजट निर्धारण वर्ष 2047 के दृष्टिकोण से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने की जरूरत के बारे में भी बात की कि देश वैश्विक कार्यबल और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहे। अर्थशास्त्रियों ने इस संवाद के दौरान, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए

महत्वपूर्ण विचारों का आदान-प्रदान किया। चर्चा का मुख्य केंद्र घरेलू बचत में वृद्धि, मजबूत अवसंरचना विकास और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से संरचनात्मक परिवर्तन को गति देना था। समूह ने अंतर-क्षेत्रीय उत्पादकता को बढ़ावा देने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की भूमिका का पता लगाया और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के निरंतर विस्तार पर भी चर्चा की। प्रतिभागियों ने कहा कि साल 2025 में अभूतपूर्व अंतर-क्षेत्रीय सुधारों की गति और आने वाले साल में उनके और सुदृढ़ीकरण से यह सुनिश्चित होगा कि भारत अपनी नींव को मजबूत करके व नए अवसरों को खोलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपना पथ प्रशस्त करता रहे।



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नववर्ष 2026 पर दी शुभकामनाएं, मजबूत भारत के निर्माण का आह्वान

नयी दिल्ली ३१/१२ (संवाददाता): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि उन्होंने नव वर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैं देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नव वर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। यह आत्मचिंतन और नए संकल्पों का भी अवसर है। इस अवसर पर आइए हम राष्ट्र के विकास, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करें। उन्होंने आगे कहा, वर्ष 2026 हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाए और एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा प्रदान करें।



इससे पहले, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नया साल महज कैलेंडर में बदलाव नहीं है; यह नए संकल्पों को मजबूत करने का अवसर है। यह नए रास्ते तलाशने, सकारात्मक बदलाव को अपनाने और बेहतर इंसान बनने के लिए निरंतर प्रयास करने का समय है। अपने संदेश में बिरला ने कहा, नए साल 2026 के आगमन पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आशा है कि आने वाला वर्ष सभी के जीवन में नए सपने, नया उत्साह, नई

संभावनाएं और भरपूर खुशियां लेकर आए। उन्होंने कहा कि आइए इस अवसर पर एकजुट होकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। आने वाले वर्ष में व्यक्तिगत प्रगति के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण के कार्य में भी सार्थक योगदान दें। स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और बढ़ावा देने का संकल्प लें, ज्योंकि स्वदेशी केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक मजबूत स्तंभ है।

नए साल के जश्न की तैयारी में दुनिया, इधर भारत ने बैक-टू-बैक दो प्रलय मिसाइल दाग दी

नयी दिल्ली ३१/१२ (संवाददाता): नए साल का आगमन होने वाला है। पूरी दुनिया जश्न की तैयारी में डूबी है। लेकिन इन तैयारियों के बीच भारत ने डबल धमाका कर दिया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए स्वदेशी रूप से विकसित 'प्रलय' मिसाइल का बेहद सफल परीक्षण किया है। यह कोई साधारण परीक्षण नहीं था,



बल्कि यह एक 'साल्वो लॉन्च' था, जिसने दुश्मन के खेमे में खलबली मचा दी है। रक्षा विशेषज्ञों की भाषा में 'साल्वो लॉन्च' का मतलब होता है एक साथ या बहुत कम अंतर पर कई हथियारों का हमला। भारत ने बुधवार को ओडिशा तट से दूर

लीगल इमरजेंसी पर ष्टीजेआई सूर्यकांत का ऐतिहासिक फैसला, इंसाफ के लिए अब 24 घंटे खुलेगी अदालत

नई दिल्ली ३१/१२ (संवाददाता): 99 भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली को लेकर अहम फैसला लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लीगल इमरजेंसी की स्थिति में कोई भी नागरिक किसी भी समय, यहां तक कि आधी रात को भी, अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है और उसके मौलिक अधिकारों पर तत्काल खतरा हो, तो अदालतें समय की बाध्यता से परे जाकर सुनवाई कर सकती हैं। उन्होंने कहा, मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट हमेशा जनता के लिए उपलब्ध रहें। नियमित कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी लीगल इमरजेंसी में व्यक्ति को न्याय मिल सके। सीजेआई सूर्यकांत ने माना कि अदालतों



में बड़ी संख्या में याचिकाएं लंबित हैं। इनके शीघ्र निपटारे के लिए अधिक से अधिक संवैधानिक पीठों के गठन की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि लंबित मामलों में स्ट्रुक्र (स्पेशल इंटींसिव रिवीजन) से जुड़े विवाद भी शामिल हैं। बिहार के बाद देश के 11 राज्यों में स्ट्रुक्र प्रक्रिया चल रही है, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी याचिका दाखिल

है। यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता और महिला अधिकारों के बीच संतुलन से जुड़ा है, जिसके लिए नौ सदस्यीय संविधान पीठ के गठन पर विचार किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों के लिए भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मामलों में लंबे समय तक चलने वाली बहस की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को निर्धारित समयसीमा के भीतर ही मौखिक दलीलें पूरी करनी होंगी और इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

केंद्र सरकार गरीबों से भोजन छीनने के लिए वीबी-जी राम जी अधिनियम लाई-मान

चंडीगढ़ ३१/१२ (संवाददाता): पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने गरीबों से भोजन छीनने के लिए वीबी-जी राम जी कानून पारित किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वंचित लोगों के अधिकारों पर डाका नहीं डालने देगी। मान ने नए 'विकसित भारत-रोजगार गारंटी आजीविका मिशन-ग्रामीण' (वीबी-जी राम जी) विधेयक को 14 घंटे के अंदर संसद में पारित कराने की कोशिशों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस अधिनियम ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित वीबी-जी राम जी अधिनियम का विरोध करने के लिए मंगलवार को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया। वीबी-जी राम जी अधिनियम ने कांग्रेस के नेतृत्व



वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संग्रम) सरकार के कार्यकाल में पारित किए गए मनरेगा की जगह ली है। मान ने सत्र के दौरान कहा कि नए अधिनियम का उद्देश्य दलितों, महिलाओं और सबसे गरीब परिवारों से भोजन, रोजगार व सञ्चमान छीनना है। उन्होंने कहा, मनरेगा को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सावधानीपूर्वक तैयार किया था। यह वर्षों की चर्चा के बाद पेश किया गया था। वहीं, वीबी-जी राम जी अधिनियम को संसद में कुछ ही घंटों में पारित कर दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार को जनविरोधी नीतियों को अपनाने के प्रति आगाह किया और कहा कि ऐसा करने पर पंजाब के लोग केंद्रीय नेताओं को उनके गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे।

बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार, एक और युवक की हत्या

ढाका ३१/१२ (संवाददाता) बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मयमनसिंह जिले में एक और हिंदू युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, बिजेंद्र विश्वास नामक युवक की नोमान मियां नाम के शख्स ने हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नोमान मियां को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इसी जिले में महज 10 दिन के भीतर हिंदू युवक की हत्या का यह दूसरा मामला है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में भीड़ द्वारा हत्या (मांस लिंगिंग) की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। राजबाड़ी जिले में 24 दिसंबर को 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट की भीड़ ने

पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। स्थानीय लोगों ने उन पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। इससे पहले 18 दिसंबर को मयमनसिंह के भालुका इलाके में दीपू चंद्र दास की भी इसी तरह हत्या की गई थी। उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने न केवल उन्हें पीटा, बल्कि उनके शव को फंदे से लटकाकर जला दिया। दीपू हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनस ने पीडित परिवार की जिम्मेदारी उठाने का भरोसा दिया है देश में 12 दिसंबर से अशांति का माहौल बना हुआ है। दरअसल, छात्र नेता उस्मान शरीफ हादी को गोली मारी गई थी, जिनका सिंगापुर में इलाज के दौरान निधन हो गया।

दिल्ली विधानसभा

नयी दिल्ली ३१/१२ (संवाददाता): दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण पर चर्चा होगी और सरकार प्रस्ताव भी लाएगी। दिल्ली विधानसभा का चार दिन का सत्र 5 से 8 जनवरी तक आयोजित होगा। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद ने फैसला लिया है कि दिल्ली के प्रदूषण पर दिल्ली विधानसभा में विस्तार से खुली चर्चा होगी और सरकार खुद प्रदूषण और पर्यावरण पर प्रस्ताव लेकर आएगी। इसके अलावा %शीश महल% (पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का आवास), दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज पर भी सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी। मंत्री ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति कैसी है, ज्यों

है, ज्या कारण हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो-जो ऐफिडेविट पुरानी सरकारों ने दिए थे, उन पर ज्या कार्रवाई हुई, उनका स्टेटस ज्या है, इन सब पर सभी सदस्य चर्चा करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 20 वर्षों की स्थिति और वैज्ञानिक रिपोर्ट्स सदन में रखी जाएगी। प्रदूषण से जुड़ी कमियां और भविष्य की कार्ययोजना पर खुली चर्चा होगी। सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से भी अपील की कि वो उनकी सरकारों ने पिछले 10-12 साल में प्रदूषण कम करने के लिए जो-जो कदम उठाए, उस सबका लेखा-जोखा लेकर विधानसभा आए। मिश्रा ने कहा कि आगे प्रदूषण कम करने के लिए ज्या-ज्या किया जा सकता है, उस पर निर्णय भी विधानसभा में सर्वसम्मति से

का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से



लिया जाएगा। कपिल मिश्रा ने बताया कि सीएजी की एक रिपोर्ट, जो पिछली सरकार के कार्यकाल में आ गई थी, मगर पिछली मुख्यमंत्री ने रोककर रखा था, उसे भी हम पटल पर रखेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी सरकार की 10 महीने के कार्यकाल की नाकामियों पर धेरेंगे। %आप% विधायक दल के चीफ व्हीप संजीव झा ने

कहा कि बीजेपी सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपये नहीं देकर अपने ही प्रधानमंत्री को झूठा साबित कर दिया। दस महीने में बीजेपी सरकार बड़ी-बड़ी बातें करने के अलावा ना दिल्ली की हवा साफ कर पाई और ना यमुना का प्रदूषण ही कम कर पाई। संजीव झा ने कहा कि छठ पर्व पर बीजेपी ने सबको यमुना में डुबकी लगवाई और आचमन कराया था, लेकिन अब पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह कह रहे कि यमुना का

पानी नहाने के लायक नहीं है। संजीव झा ने कहा कि अब बीजेपी सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन 10 महीनों में दिल्ली की जनता के हित में ज्या काम किया? अपने घोषणा पत्र में झूठे वादे करके सरकार बना ली। बीजेपी ने वादा किया था कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति महीने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक चुनावी सभा में दिल्ली की महिलाओं से यह वादा करके गए थे, लेकिन वादा झूठा साबित कर दिया।

सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित दिसंबर रहा है। ऐसा ज्यों हुआ, जबकि अब तो पराली भी नहीं जल रही है। संजीव झा ने कहा कि विधानसभा सत्र में हम सरकार से इन 10 महीनों के कामकाज का हिसाब-किताब लेंगे।

दिल्ली की रेखा गुप्ता की 10 महीने की सरकार के कामों का प्रदेश बीजेपी ने सराहना की है। मंगलवार को प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार ने केवल 10 महीने में दिल्ली में विकास की नई शुरुआत की है, जो पिछले कई सालों से उप था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा विरासत में छोड़ी गई प्रदूषण की समस्या को छोड़ दें तो बाकी सभी काम के मामले में झट्ठकसरकार का प्रयास साफ दिख रहा है।

मेरी हत्या होती है तो सपा होगी जिमेदार..., अखिलेश यादव पर पूजा पाल ने लगाए गंभीर आरोप

लखनऊ ३१/१२ (संवाददाता): समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के कुछ दिनों बाद, चायल विधायक पूजा पाल ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर उन पर उन्हें बीच रास्ते में अपमानित करके और छोड़कर संगठन के भीतर आपराधिक तत्वों को मजबूत करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि उनका निष्कासन न केवल एक व्यक्तिगत मामला है, बल्कि राज्य के पिछड़े वर्गों, दलितों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की चिंताओं को दबाने का एक प्रयास भी है। पाल ने लिखा कि उनके स्पष्टीकरण से एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों को यह जवाब मिल जाता कि ज़्या अखिलेश यादव वाकई पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों (पीडीए) के



रक्षक हैं। निकाल दी गई विधायक ने अपने एजस अकाउंट पर अखिलेश यादव को संबोधित पत्र साझा करते हुए लिखा कि अन्याय और विश्वासघात के खिलाफ मेरी आवाज़!

पार्टी से निष्कासन सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, बल्कि उज्जर प्रदेश के पिछड़ों, दलितों और गरीबों की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। मैंने न्याय की लड़ाई लड़ी है और लड़ती रहूँगी। पूजा पाल ने आगे कहा

कि वह सपा में इसलिए शामिल हुई ज्योंकि उनका मानना है कि यह पिछड़े समुदाय को न्याय दिला सकती है। हालाँकि, सपा सरकार के दौरान अपने पति की हत्या के लिए न्याय पाने की उनकी कोशिशों को निराशा ही हाथ लगी। बसपा विधायक राजू पाल की 2005 में प्रयागराज में पूजा पाल से शादी के कुछ ही दिनों बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फरवरी 2023 में, हत्या के एक प्रमुख गवाह उमेश पाल

की प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा शासन में उज्जर प्रदेश सरकार की प्रशंसा दोहराते हुए, पूजा पाल ने ज़ोर देकर कहा कि भाजपा सरकार के दौरान ही लंबे समय से लंबित न्याय मिला। पाल ने पार्टी से अपने निष्कासन पर भी सवाल उठाया, कथित तौर पर राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट देने के कारण, जबकि अखिलेश यादव ने खुद कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल जलब के चुनावों में भाजपा उम्मीदवार को वोट दिया था।

पाल ने सपा प्रमुख की उनके अहंकार के लिए आलोचना की, जिसके कारण उन्होंने एक पिछड़े समुदाय की विधवा को पार्टी से निकाल दिया। निष्कासित विधायक ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया

पर बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है और जान से मारने की धमकियाँ भी मिल रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि अपने पति की हत्या का न्याय पाने का उनका एकमात्र उद्देश्य पूरा हो गया है और अब अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपने पत्र के अंत में लिखा कि अगर उन्हें कुछ भी होता है, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इससे पहले, चायल से सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अनुशासनहीनता दिखाने, खासकर उज्जर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज़ीरो टॉलरेंस नीति की प्रशंसा करने जैसे कारणों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।

असीम मुनीर की गीदड़भभकी पर राम माधव की दो टूक, परमाणु ज़लैकमेल से कोई भी भारत को नहीं डरा सकता

नयी दिल्ली ३१/१२ (संवाददाता): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता राम माधव ने शनिवार को पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर द्वारा भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया और कहा कि इस तरह की धमकी से कोई नहीं डरता और भारत में ऐसी धमकियों का जवाब देने की समझ है। कुछ दिन पहले अमेरिका यात्रा के दौरान मुनीर द्वारा की गई इस टिप्पणी का विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध किया था और नई दिल्ली ने इस तरह की बयानबाजी जारी रखने पर दर्दनाक परिणाम भुगतने की



चेतावनी दी थी।

आरएसएस नेता राम माधव ने एएनआई से कहा कि मुनीर की परमाणु धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने इसका उचित जवाब दिया है। परमाणु ज़लैकमेल से कोई भी भारत को नहीं डरा सकता। अगर नौबत आ गई तो ज़्या किया

जाए? भारत की भी अपनी समझ है। इस सवाल का जवाब देते हुए कि ज़्या अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी टिप्पणियों का समर्थन कर रहा है, आरएसएस नेता ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उतने सहज नहीं हैं जितना पहले सोचा गया था, और वे बड़े लेन-देन वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने आगे कहा

कि भारत को भावुक होने और ट्रंप के तरीके से निपटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे दूसरे देश भी अपने तरीके से निपटते हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत भावुक लोग हैं, हम ट्रंप के तरीके को ज्यों नहीं समझ पा रहे हैं?

ट्रंप ने खतरनाक उज्जर कोरिया के तानाशाह किम जोंग-उन के साथ भी संपर्क बनाए रखा है, सिंगापुर में उनसे बात की है और कहा है कि वे दोस्त हैं। इसी वजह से उज्जर कोरिया और अमेरिका के रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया। बस यूँ ही, वह (डोनाल्ड ट्रंप) सोचते हैं कि बुरे लोगों के साथ काम करके मैं उन्हें ठीक कर दूँगा।

ट्रंप द्वारा बार-बार टैरिफ लगाने की धमकी और भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम समझौते के झूठे दावों के बारे में माधव ने कहा, ट्रंप उतने सरल नहीं हैं जितना हम पहले

सोचते थे।

वह एक बड़े लेन-देनवादी व्यक्ति हैं और उनके दिमाग में यह स्पष्ट है कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं, वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यही उनका लक्ष्य है। अफगानिस्तान में युद्ध के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेश मुशर्रफ से हाथ मिलाया था, इसका जिक्र करते हुए माधव ने कहा, वह मुनीर के साथ ऐसा कर रहे हैं, हम इसका पूरी तरह विरोध करते हैं, लेकिन अमेरिका ने (परवेश) मुशर्रफ के साथ भी यही राजनीति की थी, वह मुशर्रफ आतंकवाद का इतना समर्थन करते थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध के लिए मुशर्रफ से हाथ मिलाया था, तब भी हमने इसका विरोध किया था। अपने हितों को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की एक खास शैली है।

द्रमुक का अमित शाह से सीधा सवाल- काला कानून सिर्फ विपक्ष के लिए ज्यों?

नयी दिल्ली ३१/१२ (संवाददाता): केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान संशोधन विधेयक सहित कई मुद्दों पर द्रविड़ मुनेत्र कणगम (द्रमुक) और उसके अध्यक्ष एम. के. स्टालिन की आलोचना किए जाने के बाद, तमिलनाडु की सज़ारूढ़ पार्टी ने पलटवार करते हुए एक बार फिर अपना रुख दोहराया है कि यह एक “काला” विधेयक है।

द्रमुक के उप महासचिव एवं लोकसभा सदस्य ए. राजा ने केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तिरुक्कुरल का जिक्र किया, लेकिन इससे भाजपा को वोट नहीं मिलेंगे। शाह ने पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन पर निशाना साधा और कहा कि स्टालिन को 130वें संविधान संशोधन विधेयक को “काला विधेयक” कहने का कोई अधिकार नहीं है, ज्योंकि उन्होंने स्वयं “काले कारनामे”



किए हैं। इस विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए जाने और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद से हटाए जाने का प्रावधान है जिसका विपक्ष कड़ा विरोध कर रहा है। शुक्रवार को द्रमुक द्वारा जारी एक बयान में ए. राजा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट में 28 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और 39 प्रतिशत कैबिनेट सदस्यों की “आपराधिक पृष्ठभूमि” है राजा ने सवाल किया, “ज्या यह कानून उन पर भी लागू होगा? ज्या आप ऐसे कानून को ‘काला कानून’ नहीं कहेंगे, जिसे केवल उन लोगों को सज़ा से हटाने

के लिए लाया गया है जिन्हें वे (भाजपा) पसंद नहीं करते? अगर यह एक अच्छा विधेयक है, तो यह केवल भाजपा पर ही ज्यों लागू नहीं होता?” राजा ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को डराने के लिए यह विधेयक लेकर आई है, और जब स्टालिन ने इस “तानाशाही और काले कानून” के खिलाफ आवाज उठाई, तो इससे अमित शाह घबरा गए और “झूठ का पुलिंदा” पेश करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने द्रमुक सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताने के लिए भी शाह की आलोचना की और कहा कि उन्होंने 2016 और 2018 में अनाद्रमुक सरकारों के खिलाफ भी ऐसी ही टिप्पणियाँ की थीं।

कुछ भी करो, हंगामा करो, बस हेडलाइन बटोरना है... विपक्ष और राहुल गांधी पर जमकर बरसे किरेन रिजिजू

नयी दिल्ली ३१/१२ (संवाददाता): संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार व्यवधान देखने को मिलने के बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा की अनुमति देने का लगातार आग्रह किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा गला भी बैठ गया देखो। विपक्ष को चिल्ला-चिल्ला के मैं अनुरोध करता हूँ कि बहस होने दीजिए। एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में, रिजिजू ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में, संसद विपक्ष की होती है ज्योंकि वे सरकार से जवाब मांग सकते हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। विपक्ष को सवाल



पूछने होंगे। अगर सवाल पूछने वाले ही भाग जाएं तो सरकार ज्या करेगी? हम उनसे हंगामा न करने के लिए कह रहे हैं। मेरा गला खराब हो गया ज्योंकि मुझे चिल्लाना पड़ा और विपक्ष से हंगामा न करने के लिए कहना पड़ा। गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे पीएम, सीएम, मंत्रियों को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा बिल फाइने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन लोगों को ऊपर से ऑर्डर दिया है, उनके पार्टी के नेताओं ने कुछ भी करो,

पीएम-सीएम को बर्खास्त करने वाले विधेयक पर बंट गया विपक्ष? टीएमसी का जेपीसी में शामिल होने से इनकार

कोलकाता ३१/१२ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को बर्खास्त करने संबंधी विधेयकों की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में किसी सदस्य को नामित नहीं करेगी, यदि उन्हें लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है या गिरफ्तार किया जाता है। टीएमसी ने एक बयान में कहा कि हम 130वें संविधान संशोधन विधेयक का पेश होने के चरण में ही विरोध करते हैं और हमारे विचार से जेपीसी एक दिखावा है। इसलिए, हम एआईटीसी से किसी को भी नामित नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन विवादास्पद विधेयक- संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर



पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 - पेश किए। हालांकि, इन तीनों विधेयकों के पेश होने पर सदन में भारी हंगामा हुआ और विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इन विधेयकों के ज़रिए गैर-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य सरकारों को अस्थिर करना चाहती है। कुछ विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों की प्रतियां फाड़कर शाह की ओर फेंक दीं, जिन्होंने बाद में कहा कि विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा। शाह द्वारा संसद में इन विधेयकों को पेश किए जाने के बाद, ममता बनर्जी ने कहा कि ये विधेयक देश में लोकतांत्रिक युग को %खत्म%

कर देंगे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को सशक्त करेंगे और इसे सुपर-आपातकाल से भी बड़ा कदम बताया। उन्होंने एजस पर पोस्ट में कहा कि मैं भारत सरकार द्वारा आज पेश किए जाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक की निंदा करती हूँ। मैं इसे सुपर-आपातकाल से भी बढ़कर, भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में एक कदम बताकर इसकी निंदा करती हूँ। यह कठोर कदम भारत में लोकतंत्र और संघवाद के लिए मौत की घंटी है।

अलग अंदाज में दिखे राहुल गांधी, गाड़ी से उतरकर खेतों में पहुंचे, मखाना किसानों से की मुलाकात

कटिहार ३१/१२ (संवाददाता): लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान शनिवार को कटिहार में मखाना किसानों से उनके खेतों में मिले। तस्वीरों में राहुल किसानों के साथ तालाब में उतरते और उनसे बातचीत करते नज़र आ रहे हैं।

गौरतलब है कि बिहार मखाना उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है और भारत के कुल मखाना का लगभग 80 प्रतिशत यहीं पैदा होता है। इससे पहले, शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव, जो भागलपुर में राहुल के साथ %मतदाता अधिकार यात्रा% में भी मौजूद थे, ने कहा

कि आगामी चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आखिरी चुनाव होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा। वह दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।

आपको असली मुख्यमंत्री चाहिए या नकली? हम सभी को एकजुट होकर बदलाव के लिए वोट करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर चलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्वा पर एक पोस्ट में कहा कि %मतदाता अधिकार

यत्रा ने लोगों को जगा दिया है और मौजूदा सरकार जनादेश से नहीं, बल्कि चोरी से बनी है। पोस्ट में लिखा था, वोट चोर सरकार को देखिए - यह बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ गुस्सा है। यह आक्रोश दो दशकों की गरीबी और पलायन के खिलाफ है। यह क्रांति मताधिकार की चोरी के खिलाफ है।

यह एक जन आंदोलन है - लोग जाग गए हैं और समझ गए हैं कि चोरी से बनी सरकार जनता की सरकार नहीं होती। इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि वह 29 अगस्त को बिहार में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार रैली में शामिल होंगे।

हंगामा करो, और सुर्खियाँ बटोरो।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुर्खियाँ बटोरने के लिए बकवास बोलते हैं लेकिन वह वोट बैंक में तज्ज्दिल नहीं होगा। जिस तरह से वो (कांग्रेस) देशविरोध का काम करते हैं, देश के लोग कभी भी कांग्रेस को सज़ा में नहीं लाएँगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को किसी ने एक नोट लिखकर दे दिया

कि ये बोलो। बोलते-बोलते वो भटक ?? गए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी बुरी तरह हार गए। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची में संशोधन करने और झूठे नाम हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने इसकी माँग की। महाराष्ट्र के आँकड़े गलत साबित हुए, और अब वे माफ़ी माँग रहे हैं... अब, किसी ने राहुल गांधी को एक नोट दिया कि ज़्या बोलना है। वे

बोलते-बोलते भटक गए।

कलिंग समाचार

THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)

PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com



विविध समाचार



चेहरे के दाग-धब्बों से छुटकारा दिलाता है अंजीर



इस दुस्त भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। अंजीर खाने के भी कई फायदे हैं। आयुर्वेद के चिकित्सक डॉ. प्रमद के मुताबिक अंजीर खाने से किसी भी प्रकार के दाद से छुटकारा पाया जा सकता है। नियमित रूप से अंजीर खाकर कब्ज की समस्या से राहत पाया जा सकता है। इसके अलावा रक्त को पानी में घो से सोन अंजीर भिगोकर रखें। इसे रोजाना मुँह उलकर खा लें। इससे कब्ज पानी हल्के से खुली समस्या से निजात पाया जाता है।

अंजीर खाने के फायदे

- 1-अंजीर का पेस्ट बनाकर भी अपने चेहरे पर लगा सकती हैं। इसे 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगाए रखें। मुख के बाद चेहरा भी लें। इससे आप चेहरे के सभी दाग धब्बे निकल आते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे दूध में भिगोकर भी खा सकते हैं। इससे चेहरे के दागों का काल-मुहूर्तों से मुक्ति मिलती है।
- 2-अंजीर में फायोफेरस, फिटोनिन जी और कैल्शियम पाया जाता है। ये सभी तत्व आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं। जिन महिलाओं को उम्र 50 पर कर चुकी है, उन्हें अक्सर ओस्टियोपोरोसिस और पीठ में दर्द की शिकायत होती है। ऐसी महिलाओं को निश्चित रूप से अंजीर को अपनी डाइट चार्ट में शामिल करना चाहिए।
- 3-सुखे अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर पाए जाते हैं। प्राकृतिक अंजीर में सुखे अंजीर के तुलना में कम एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण होते हैं।

विरासत में मिला पैसा

बच्चे के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है

हर माँ-बाप को अपने बच्चों से प्यार होता है। वे उनकी परवरिश का पूरा खयाल रखते हैं। उनकी खुशी का खयाल करते दम तक होता है। वे अपनी संर्पित खोदकर जाना चाहते हैं कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं हो। लेकिन हर शहर इतना खुशकिस्मत नहीं होता। मतलब कुछ माँ-बाप के पास बच्चों के नाम खोदने लायक कुछ बचता हो नहीं।

कुछ बच्चे (बुच्चा, या अर्धेष्ट) ऐसे होते हैं कि विरासत उनकी कीमत बचा देती है, यानी सेल्फवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। समाज उनकी हर कामगारी को उनकी मेहनत नहीं बल्कि विरासत से जोड़कर देखने लगता है। इन सबके चलते उन्हें शर्म, अपराधबोध और दुविधा महसूस होने लगती है। वे खुद को अलग-थलग महसूस करने लगते हैं।

कई बार लोग जाने-अनजाने जलने लगते हैं और उनके प्रति व्यवहार में अक्सर जलने भी लगते हैं। कई बार ये बच्चे की सह जलन उनके प्रति एक घृणा का रूप ले लेती है। विरासत में बुद्धि से संर्पित पाने वाला बेकसूर सख्त भी आम लोगों से कटा-कटा रहने लगता है। उनकी कोशिश होती है कि वह ऐसे लोगों के बीच उठे-बैठे, जिन्हें विरासत में मिली उनकी संर्पित से कोई फर्क नहीं पड़ता।

विरासत में संर्पित पानेवाले ऐसे सख्त के मन में क्या चलता रहता है, यह जानने के लिए बारकाई चाहिए। इनमें से प्रत्येक बच्चे की अपनी कहानी है। उनके पिता की विरासत में उन्हें कुछ मिलता है। उनके पिता की विरासत में उन्हें कुछ मिलता है। उनके पिता की विरासत में उन्हें कुछ मिलता है। उनके पिता की विरासत में उन्हें कुछ मिलता है।



कि विरासत में मिली संर्पित का संपूर्णयोग कैसे कर सकते हैं। पैसों की किसी ट्रस्ट में डालने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर बकसद एक माँ हो।

अगर बच्चा चाहता है कि वह कुछ संर्पित समाज के साथ रोकर करे या अच्छे काम के लिए दान करे तो उनकी इसके लिए तैयार करना चाहिए। स्टडी से पता चला है कि लोग विरासत में मिली संर्पित अपनी प्रकृति के हिसाब से भौतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्य कर रहे हैं।

भौतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। भौतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। भौतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। भौतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। भौतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्य कर रहे हैं।

हैं। ऐसे काम की लिस्ट बनाने में बच्चे की मदद करना चाहिए।

होसता, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे विरासत और पर ध्यान दें। विरासत में अपार संर्पित पाने वालों के लिए कुछ ऑनलाइन स्कूल भी हैं। जहाँ वित्तीय फैसले लेने, उसके गणना मुकाम, बॉन्ड, फीस, वैक्यूएशन कंप्लायंस वगैरह के बारे में बताया जाता है। बच्चा अगर बकसद जटिल कार्य के लिए विशेषज्ञ की मदद ले सकता है लेकिन अपनी जल्दगी को समझने के लिए वित्तीय रूप से साक्षर होना भी जरूरी है।

बीबी, जब विरासत में संर्पित मिलती है तो दोस्तों रिश्तेदारों का संर्पित बढ़ जाता है। इनमें बाढ़फारी, साजिश करनेवालों, धिना ग्राज उधार मारने वाले अच्छी खासी की तादाद होती है। उधार लेने वालों में भी कई ऐसे होते हैं जो वह मान बैठे होते हैं कि वह बीबी-सी अपनी कमाई दे रहा है। ऐसे में पैरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चों को कुछ रकम देकर भुल जाना भी सिखाएं।

ये सपरफूड भी बढ़ा सकते हैं कद



ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पाला-पिता छोटे कद के हैं तो आप पर भी उसका असर पड़ता है और आप भी छोटे रह जाते हैं। इसके अलावा लोग ये भी सोच रखते हैं कि किसीराकबका के बाद लंबाई बढ़ना नामुमकिन है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप लंबा होना चाहते हैं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको बस अपने खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत है।

शालजम : शालजम में लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन होते हैं। नियमित रूप से इसे खाने से आपकी लंबाई बढ़ सकती है। इसके लिए आप इसकी सब्जी बनाकर या इसका जूस पी सकते हैं। कुछ ही महीने में आपकी कुछ इंच लंबाई बढ़ जाएगी। फलियाँ : फलियाँ पानी बीस में फाड़कर, प्रोटीन, विटामिन और कार्बीहाइड्रेट से भरपूर होती हैं। रोज इसे खाने से शरीर हार्मोन पर प्रभाव पड़ता है।

भिंडी से भी बढ़ाई जा सकती है लंबाई

मटर

शरीर जल्दबाई हैमोरी हो लेकिन मटर के दानों में भी लंबाई का राज छुप है। रोजाना भंडान में मटर खाने से असर दिखेगा।

भिंडी

अच्छातर लोग भिंडी खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसके फायदे से अनजान हैं। इसकी सब्जी खाने से लंबाई के हार्मोन प्रभाव करने लगते हैं। जिससे आपकी लंबाई बढ़ती है।

पालक

जिस तरह पालक सेहत के लिए फायदेमंद है। उसी तरह लंबाई बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सब्जी या जूस के रूप में लेने से लंबाई में फर्क दिखेगा।

लैपटाप की बैटरी लाइफ को बढ़ाने के ये हैं कुछ आसान उपाय

लैपटाप हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, लैपटाप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफी आसान होता है। इसके जरिए आप कहीं भी बैठकर अपने सारे काम आसानी से कर सकते हैं, ज्यादातर कॉर्पोरेट जगहों पर भी लैपटाप 4 से



इस्तेमाल पर निर्भर करता है, अगर हम आपको आपके लैपटाप की बैटरी लाइफ को बढ़ाने के कुछ आसान उपाय बताएंगे, तो आप लैपटाप की बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं।

तापमान का रखें ध्यान

ज्यादा तापमान और बढ़ती उम्र धीरे-धीरे बैटरी की परफॉर्मंस को कम कर देते हैं। कम तापमान (30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न हो) में डिवाइस का इस्तेमाल करने से उसकी लाइफ साइकल बेहतर होगी, अगर आपने डिवाइस को गर्मी से बचाने की कोशिश करें, स्मार्टफोन के ज्यादा गर्म होने की समस्या से परेशान होना बर्बाद है, लैपटाप में इस बात का ध्यान रखें कि अगर कूलिंग गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि लैपटाप में गर्म होना आसानी से निकल जाए, धूल के कारण

मुफ्त ऐप से करें

विज्ञापन के साथ आने वाले ऐप्स आपके डिवाइस की बैटरी लाइफ को कम कर देते हैं, लेकिन अगर आपको उस पर कोई विज्ञापन जरूर आए, तो समझ लीजिए कि वह बैटरी और प्रोसेसर पर असर डालेगा ही, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वाई-फाई का कनेक्शन ऑफ कर दें।



यदि आप सारा दिन कम्प्यूटर के सामने बैठकर लगातार काम करते हैं, या किसी कॉफी सेंटर में पूरा दिन फोन पर बात करते हैं, तो जरा ध्यान दें। लगातार बैटरी काम करते रहना, शरीर पर भारी पड़ सकता है। कम्प्यूटर के अतिरिक्त इस्तेमाल से कलान्धरी और हार्ड पर दबाव के कारण 'कार्बन डनल सिंड्रोम' बीमारी बढ़ती जा रही है। इसमें शुरुआत में दर्द होता है, हार्ड में इनफ्लेमेट होती है और हाथ सूख लगते हैं। उम्रवालों को सोने या मुड़ी बंद करने में परेशानी होती है। वहीं, बच्चों का

लरीका यदि सही नहीं है तो कंधे, गर्दन और पीठ को नुकसान हो सकता है। लंबे समय तक कम्प्यूटर के सामने बैठे रहने से आंखों के झगड़ों में जलदी धुंधल होने लगती है। लगातार स्क्रीन की ओर देखते रहने से चलाचल का दबाव भी कम हो जाता है। इसके चलते नजर कमजोर होना, मिर दर्द और चक्कर जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बिना किसी से बातचीत किए लगातार कई घंटों तक कम्प्यूटर पर काम करते रहने पर धक्का और तनाव के कारण 'एरोसि सिंड्रोम' होने का डर है। इसमें भूख न लगना, बिजुबिहास और नींद न आने की टिकटें पर होती हैं।

काम करते समय सहज रहना आवश्यक है। इस दिशा में पहला कदम है ऑफिस के 5 मुख्य नियमों को जानना। 1. शरीर को ठीका खोड़कर धीरे-धीरे लंबी सांस लीजिये। 2. कार्य को सरल बनाएं। एक समय में एक ही काम करें। 3. काम सॉल्यूशन और एकाग्र हो कर करें। 4. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनावग्रस्त न हों। 5. आवश्यकतानुसार बीच-बीच में विश्राम करें।

छोटे कदम, बड़ी राहत

» देर तक ऑफिस में काम करने के कारण हो सकता है शारीरिक व्यायाम के लिए समय ही न बचता हो। ऐसे में शारीरिक व्यायाम के अन्य विकल्प खोजने आवश्यक हैं।

» किसी प्रोजेक्ट पर सहयोगी के साथ विचार-विमर्श करना है, तो यह काम बैठकर करने के बजाय, चलते हुए कर सकते हैं।

» टेलीफोन पर खड़े होकर बात कीजिये।

» ऑफिस में किसी से बात करनी हो तो फोन के बजाय उसके पास जाकर बात करें।

» लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें।

» बिजनेस टिप पर हों तो ऐसे होटल में रुकें जहाँ स्विचिंग पुल अथवा फिटनेस सेंटर हो।

» एयरपोर्ट पर क्लाइंट की प्रतीक्षा करते समय बैलिंग नहीं, ठहलते रहिए।

» अपने सुटकेस में कूटने की रस्मी रखें। होटल में समय मिलने पर अपने कमरे में रस्मी कूटिये।

» प्रोएकर कार्यों के लिए थोड़ा समय निकालिये।

» कार्यस्थल के सभी किसी फिटनेस सेंटर के सदस्य बन जाएं। काम से पहले, बाद में वहाँ व्यायाम कर सकते हैं।

» बिजनेस कैलेंडर में व्यायाम का समय निर्धारित कर लें। महत्वपूर्ण कार्य को तब तक छोड़ें जब तक कि आप कैलेंडर पर अंकित कर लें। थोड़ा



» बस से उतरते जाते समय आधे आगे समय थोड़ा पहले उतर जायें और बाकी का रास्ता पैदल चले।

» लंच ब्रेक अथवा समय मिलने पर अपने ऑफिस के इन्-विन्डो ही चकरा कर लें। थोड़ा

स्ट्रेचिंग कर सकते हैं।

» इन सबक-चलते नियमों का अनुपालन करके हम तनावमुक्त रहकर पूरा दिन आनन्दपूर्वक व सक्रिय के साथ व्यतीत कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य को स्वस्थता बनाती है।



लोकेशन ट्रैकिंग बंद कर दें

हम ही में आई एक रिपोर्ट में बताया किना गया है कि फेसबुक ऐप डिवाइस को बैटरी को जल्दी खत्म करता है क्योंकि यह बार-बार लोकेशन मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करके यूजर की लोकेशन जाना रहता है, ऐसे में बिना ऐप को आपके लोकेशन को जल्द कर दें, उनके लोकेशन ट्रैकिंग को ऑफ कर देंगे से जल्द मदद मिलेगी,

पूरी तरह वाई से बेहतर है थोड़ा-थोड़ा वाई करें

बैटरी को 100 फीसदी से खेपे लें जाकर शून्य पर खत्म करने से बेहतर है कि आप इसे 50 फीसदी तक ही डिस्चार्ज होने दें, 30 से 40 फीसदी के बीच का ठहान बनाए रखें, ऐसा करने से आपके बैटरी की लाइफ तीन गुना बढ़ जाएगी, बैटरी को कई साल तक इस्तेमाल करने योग्य बनाने कि लिए, लोकेशन को मुहज है कि आप चार्जिंग का पैर 40 फीसदी से शुरुआत और 50 फीसदी पर बंद, तब का दें,

डिस्क की साइनेस कम रखें

यह सुझाव लैपटाप और मोबाइल डिवाइस पर लागू होता है, डिवाइस के इनफ्लुएंस रहने पर आपके डिस्क की जल्दी देर तक आने रहे, यह काम करने और डिस्क की साइनेस कम करने की आप थोड़ा बैटरी बचा सकते हैं,

वाई करते वक या वाई-फाई पर ऐप अपडेट करें

आपकी पर कोई भी एप्लिकेशन जिससे प्रोसेसर या बैटरी पर दबाव पड़ता है, वह ज्यादा ही सीपीयू पावर लेगा, ऐसे से बेहतर यह होगा कि एप्लिकेशन आप तब पर स्थिर रहे और आप मोबाइल डेटा इंटरनेट के बजाय वाई-फाई का इस्तेमाल करें, आप अपने ऐप अपडेट को वाई-फाई पर शेड्यूल करें, अगर आपके डिवाइस में विकल्प मौजूद है तो सिर्फ वाई-फाई को ही अपडेट कर बैटरी लाइफ को बचा सकते हैं,

फ्लाइंग मॉड का इस्तेमाल करें

अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ कोई नेटवर्क नहीं है तो बेहतर होगा कि आप फ्लाइंग मॉड (फ्लाइंग मोड) को ऑन करें क्योंकि इसका जोर ऐसी जगहों पर वाई-फाई के बजाय तब तक करेगा जिसका जोर बैटरी लाइफ पर पड़ेगा,

लैपटाप से एक्सटर्नल ड्राइव को अलग रखें

अक्सर देखने में आता है कि लैपटाप यूजर स्कडिवाइस जैसे पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को लगातार अटैच करते हैं और अटैच ही रखते हैं, ये डिवाइसेस बैटरी के पावर को लगातार पावर को कम करती हैं, ऐसे में जब भी एक्सटर्नल डिवाइस का काम पूरा हो जाए तो उन्हें फ्लाइंग लैपटाप से रिमूव कर दें,

इन सुझावों का इस्तेमाल कर आप अपने फोन को पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर बैटरी लाइफ दे सकते हैं,

कलिंग समाचार



संपादकीय

गुरूवार 01 जनवरी 2026

नीतीश और भाजपा का नकाब खिंच गया

बिहार में एक ऐसी घटना घटी जिसने महिला अस्मिता की रक्षा के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मु यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। इस दौरान अपना नियुक्ति पत्र लेने आई महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब उन्होंने सबके सामने मंच पर ही खींच लिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया और कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार ने पूरे होशो हवास में हिजाब पहनी महिला का अपमान किया। हिजाब खींचने की अभद्रता की। एक पल को इस घटना को हिंदू–मुस्लिम नजरिए से हटकर देखें तो यह वैसा ही कुकृत्य है मानो किसी महिला का घूँघट उसकी अनुमति के बिना उठा देना या किसी का दुपट्टा खींच देना। हद तो यह है कि इस घटना पर माफी मांगना तो दूर नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू या उनकी सहयोगी भाजपा ने अब तक इस पर अफसोस तक नहीं जताया है। बल्कि इसे मामूली घटना बताकर चलता किया जा रहा है। मु यमंत्री को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि वे यह देख रहे थे कि जिसे नियुक्ति पत्र मिल रहा है, वह सही व्यक्ति है या नहीं। इससे ज्यादा लचर तर्क नहीं हो सकता, क्योंकि मु यमंत्री के कार्यक्रम में जाने से पहले बाकायदा कई स्तरों पर सुरक्षा होती है, पहचान पत्र देखे जाते हैं और जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलना था, वो कौन हैं, इसकी भी शिना त हुई होगी। अगर नीतीश कुमार को फिर भी पड़ताल करनी थी, तो वे नुसरत परवीन को हिजाब हटाने कह सकते थे, लेकिन खुद बढ़कर हिजाब खींचना अक्ष य है। कांग्रेस ने तो इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। राजद,पीडीपी, सपा समेत कई दल नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं। जबकि अखिल भारतीय मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है, साथ ही न्यायपालिका को इस मामले में दखल देने की अपील की है। दूसरी तरफ उत्तरप्रदेश में केबिनेट मंत्री संजय निषाद ने तो नीतीश कुमार के बचाव में कह दिया कि बुर्का उतरने पर इतना बवाल हो गया, अगर कहीं और छू देते तो क्या होता। वो भी तो आदमी ही है ना। संजय निषाद के इस बयान पर भी विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने इस टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए लखनऊ के कैसरबाग थाने में नीतीश कुमार और संजय निषाद दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। जिसके बाद संजय निषाद का कहना है कि उनकी बात को गलत संदर्भों में लिया गया। वे तर्क दे रहे हैं कि भाषा पर पूर्वांचल के प्रभाव से उनकी बात को गलत समझ लिया गया। मान लें कि संजय निषाद को ठीक तरीके से नहीं समझा गया, लेकिन हिजाब खींचने को उन्होंने गलत नहीं माना, यह तो जाहिर ही है। संजय निषाद ने कहा है कि इस मामले पर राजनीति की जा रही है। नीतीश कुमार के काम को जनता जानती और समझती है। जनता बार–बार उन्हें समर्थन दे रही है और मु यमंत्री बना रही है। उन्होंने जो काम किया है, वह जनता के सामने है। आगे भी जनता ही तय करेगी कि उन्हें समर्थन देना है या नहीं। यानी महिला के अपमान पर आपत्ति जताने को राजनीति कहा जा रहा है। और बार–बार जीतने या 10 बार मु यमंत्री बन जाने का यह अर्थ कतई नहीं है कि नीतीश कुमार को किसी के भी साथ, कैसा भी व्यवहार करने की छूट मिली है। जीत किसी को भी मर्यादा भंग करने की इजाज़त नहीं देती। नीतीश कुमार ने पहली बार महिला विरोधी कार्य नहीं किया है। विधानसभा के भीतर उन्होंने पूर्व मु यमंत्री राबड़ी देवी की अभद्र तरीके से आलोचना की थी, इससे पहले जब वे राजद के सहयोग से मु यमंत्री थे, तब नवंबर 2023 में राज्य विधानसभा में जनसं या नियंत्रण और महिला शिक्षा के महत्व पर बोलते हुए उन्होंने विवादित बयान दिया था। उस समय उनके विरोध में बैठी भाजपा ने नीतीश कुमार के बयान को शर्मनाक और भद्दा बताते हुए माफी की मांग की थी, लेकिन आज भाजपा को नीतीश कुमार की हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। महिला आयोग भी इस मुद्दे पर चुप है। कम से कम इन पंक्तियों के लिखे जाने तक राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग ने नीतीश कुमार पर कोई एक्शन नहीं लिया है।

नित्य चक्रवर्ती

भ्रष्टाचार के उन्मूलन और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों पर जनमत संग्रह कराने के लिए बातचीत हुई। उ मीद है कि कार्की जल्द ही इस जनमत संग्रह के मुद्दे पर फैसला लेंगी। अगर वह इसे मंजूरी देती हैं, तो यह फिर से वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। 12 फरवरी, 2026 को बांग्लादेश में, राष्ट्रीय चुनावों के साथ-साथ जनमत संग्रह पर भी वोटिंग होगी।

क्या बांग्लादेश का चुनाव से पहले का माहौल नेपाल में दोहराया जा रहा है, जो इस साल सितंबर के दूसरे सप्ताह में देश के जेनरेशन जेड (जेन–जेड) द्वारा सत्ताधारी के.एस. ओली सरकार के खिलाफ दो दिन के विद्रोह का केंद्र था ? बड़े संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं, एकमात्र अंतर यह है कि बांग्लादेश में छात्र प्रदर्शनकारियों की अपनी नौ महीने पुरानी पार्टी है, लेकिन काठमांडू में, जेन–जेड के नेता और उनके मार्गदर्शक अभी भी बिना किसी औपचारिक पार्टी आधार के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं।

29 लाख की आबादी वाले देश नेपाल में सितंबर के विद्रोह के तीन महीने से ज्यादा समय बाद, अगले साल 5 मार्च को चुनाव कराने की सभी तैयारियां

कर ली गई हैं। चुनाव आयोग ने 19 लाख मतदाताओं की सूची तैयार की है और 114 राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए योग्य पंजीकृत कि या गया है। लेकिन आखिरकार, पिछले दो दशकों से हिमालयी देश पर शासन करने वाली स्थापित राजनीतिक पार्टियां ही आने वाले चुनावों में मायने रख रही हैं, विद्रोह करने वाले जेन–जेड युवाओं की ओर से पुराने सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती देने के लिए कोई मजबूत राजनीतिक गठबंधन सामने नहीं आया है, जिन्होंने दो दिनों के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री के.एस. ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करके इतिहास रचा था।

इसी तरह बांग्लादेश में, जुलाई 2024 के विद्रोह के छात्र प्रदर्शनकारियों द्वारा स्थापित नेशनल सिटीजन्स पार्टी (एनसीपी), मौजूदा चुनाव अभियान में कोई प्रभाव डालने में विफल रही है, जबकि बीएनपीऔर जमात–ए–इस्लामी जैसी स्थापित पार्टियां हावी हैं, क्योंकि 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं। नेपाल में, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को जेन–जेड प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए चुना था, ठीक

संदर्भ ढूंस कर उसे बढ़ाया जाता है, ताकि जांचने वाले को लगे कि छात्र काफी जानकार हैं, कुछ इसी अंदाज में फिल्म को एक विषय पर केन्द्रित रखने की जगह ये भी और वो भी, सब मिलाकर बनाया गया है। निर्माता–निर्देशक पहले तो शायद इसी उलझन में रहे कि भारत–पाकिस्तान के कड़वे संबंधों पर सीरीज़ बनानी है या फिल्म। क्योंकि आम फिल्मों की तरह इसमें शुरुआत, मध्यांतर और अंत नहीं हुआ। बल्कि चैप्टर वन से फिल्म शुरू हुई और आखिरी चैप्टर के आने पर भी फिल्म खत्म नहीं हुई है, अब इसका अगला हिस्सा मार्च में आएगा, इसकी घोषणा की गई है। हर चैप्टर का एक शीर्षक है और उसी हिसाब से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। खैर, इसे प्रयोग मानकर नजरंदाज किया जा सकता है। लेकिन फिल्म बनाने वाले शायद ये भी तय नहीं कर पाए कि उन्हें किस घटना, किस पात्र पर फिल्म को केन्द्रित करना है। सबसे शुरू में कंधार घटना दिखाई गई है, जहां इंडियन एयरलाइन्स के विमान को हाईजैक कर आतंकवादी ले गए थे। पाठक जानते हैं कि इस हाईजैक मामले में सात दिनों के बाद विमान से यात्रियों को छुड़वाया जा सका, जिसके लिए तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने भारत की जेल में बंद तीन खूंखार आतंकियों मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर को रिहा किया था और अपहरण करने वालों को भारी भत्कम राशि भी दी थी। इस घटना में विदेश मंत्री जसवंत सिंह और मौजूदा एनएसए अजित डोभाल सरकार की तरफ से आतंकियों के सामने गए थे। फिल्म के अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर में काल्पनिक घटनाओं और पात्रों का जिक्र है। लेकिन फिल्म में सच और कल्पना दोनों मिला दिए गए हैं। अजित डोभाल अजय सान्याल बना दिए गए हैं। जो आतंकियों से आंख से आंख

वैसे ही जैसे 8 अगस्त 2024 को छात्र प्रदर्शनकारियों ने मुह मद यूनस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मु य सलाहकार के रूप में काम करने के लिए चुना था।

अब नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री खुद थोड़ी निराश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीति में नए चेहरों के आने की संभावनाएं धूमिल हैं। उन्होंने इस उ मीद के साथ प्रधानमंत्री का पद संभाला था कि नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में अपने पूरे करियर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली होने के नाते, वह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के बाद अपना अंतरिम पद छोड़ देंगी, लेकिन हाल के दिनों में, वह पारदर्शिता पर आधारित और भ्रष्टाचार से मुक्तनए नेपाल के उदय के बारे में उ मीद खो रही हैं। हाल ही में उन्होंने आने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले भ्रष्टाचार और कार्यकर्ताओं की मांगों पर चर्चा करने के लिए नागरिक सुरक्षा अभियान टीम के साथ एक बैठक की।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन और अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों पर जनमत संग्रह कराने के लिए बातचीत हुई। उ मीद है कि कार्की जल्द ही इस जनमत संग्रह के मुद्दे

धुरंधर की उलझन

मिलाकर बात करते हैं, सात दिनों तक विमान में कैद रहने वाले आम यात्रियों से भारत मां की जय के नारे लगवाना चाहते हैं। कंधार ले जाए गए विमान में एक यात्री की हत्या आतंकियों ने की थी, जिसे बेहद वीभत्स तरीके से फिल्म में दिखाया गया है, हालांकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी।

यह वीभत्सता यहीं नहीं रुकी, आगे कई और दृश्य ऐसे आए हैं, जिनमें एक–दूसरे के खून के प्यासे इंसान दिखाने के लिए उन्हें हैवानों से भी बदतर दिखाया गया है। इन दृश्यों को पूरा देख लें तो आम इंसानों का कलेजा मुंह को आ जाए। ऐसा नहीं है कि हिन्दी फिल्मों में क़रूरता पहले नहीं दिखाई गई है। फिल्म शोले का वह दृश्य भी काफी डरावना है जिसमें गब्बर सिंह एक चैंटे को मसल देता है और दर्शक समझ जाते हैं कि इमाम साहब का नौजवान बेटा अहमद मारा गया है। कहने का अर्थ यह कि क़रूरता का संदेश संप्रेषित करने के लिए किसी की बोटी–बोटी करते दिखाना, खोपड़ी फाड़ देना, शरीर में छोटे–छोटे छेद करना जरूरी नहीं है। लेकिन धुरंधर के निर्देशक ने ऐसा ही किया है। फिल्म में संपादन का भी पूरी तरह अभाव दिखा है। कई दृश्य बेवजह लंबे खींचे गए हैं।

बहरहाल, कंधार के बाद 2001 में संसद पर किया हमला भी दिखाया गया और इसमें एक आतंकी वही है, जो विमान अपहरण में शामिल था। संसद हमले के कई असली फुटेज फिल्म में दिखाए गए हैं। एक बार फिर अजय सान्याल आते हैं जो लगातार इस कोशिश में हैं कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल हो। वे एक योजना बनाते हैं, जिसे आखिरकार अमल में लाया जाता है। धुरंधर के नाम पर चीयर्स करते हुए इस योजना

पर फैसला लेंगी। अगर वह इसे मंजूरी देती हैं, तो यह फिर से वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। 12 फरवरी, 2026 को बांग्लादेश में, राष्ट्रीय चुनावों के साथ-साथ जनमत संग्रह पर भी वोटिंग होगी। नेपाल में भी, अगर प्रधानमंत्री कार्की जनमत संग्रह के प्रस्ताव को मंजूरी देती हैं, तो 5 मार्च को ही जनमत संग्रह पर मतदान हो सकता है।

नेपाल की वर्तमान संसद में 334 सदस्य हैं – निचले सदन में 275 और ऊपरी सदन में 59 सदस्य। राजशाही खत्म होने और लोकतंत्र शुरू होने के बाद से देश में गठबंधन सरकार का चलन है। 2022 के चुनावों में, 89 सीटों के साथ नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पिछली सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार का नेतृत्व नेपाल क युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के प्रधानमंत्री के.एस.आर. ओली कर रहे थे, जिन्हें नेपाली कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियों का समर्थन प्राप्त था। सीपीएन (यूएमएल) एक और क युनिस्ट पार्टी है जो पिछले चुनावों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। क युनिस्ट पार्टियों के बीच फूट ने नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता में बहुत योगदान दिया।

अभी तक, वही पार्टियां

सामने आई हैं और प्रचार कर रही हैं। 2022 के तर्ज पर गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सभी पार्टियों में अंदरूनी समस्याएं हैं। नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व पर कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि के .एस. ओली से पिछले स मेलन में इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन वह असंतोष से निपटने में कामयाब रहे और फिर से नेता बनकर उभरे।

कुल मिलाकर, सात पार्टियों को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है और गठबंधन सरकारें उनके इर्द–गिर्द घूम रही हैं।मंजूर पार्टियों से लगभग पांचवां हिस्सा नई हैं, जिनमें से कई युवा कार्यकर्ताओं द्वारा पंजीकृत की गई हैं, जिन्होंने इस साल सितंबर में नेपाल को हिला देने वाले भ्रष्टाचार विरोधी विरोध प्रदर्शनों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। लेकिन समस्या यह है कि इन सभी छोटी पार्टियों ने अभी तक चुनाव की लड़ाई के लिए संगठन नहीं बनाए हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जेन–जेड के सक्रिय सदस्यों की ये पार्टियां चुनाव से पहले गठबंधन करेंगी जेन–जेड ने सितंबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान बेरोजगारी की समस्या के बारे में बड़े पैमाने पर बात

बताया गया है। इस काम में जिन व्यापारी बंधुओं की मदद ली गई है, वो भारत के नकली नोट छापते हैं और बताया गया है कि नकली नोट छापने के लिए करेंसी प्लेट उन्हें भारत के एक मंत्री और बेटे ने दुबई में दी है। फिल्म में एक अधिकारी अजय सान्याल को बताता है कि मंत्री और उसका बेटा लंदन से ये प्लेटें ला रहे थे और बीच में दुबई रुक गए, वहां आईएसआई और पाकिस्तानी व्यापारी को प्लेट्स दे दी गई। ये दृश्य हास्यास्पद और सच से कोंसों दूर है। भारत में नोट प्रिंट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड श के बीच अहम जि मेदारियां बंटी होती है। देवास (मध्य प्रदेश), नासिक (महाराष्ट्र), मैसूर (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिम बंगाल) इन चार जगहों पर ही नोट छापे जाते हैं। इन प्रेसों की सुरक्षा ऐसी होती है कि इसके अंदर आने की बात तो दूर, बाहर भी आसपास खड़े रहने की आम लोगों को इजाजत नहीं होती। कुछ अनुमति प्राप्त उच्चाधिकारी ही इन प्रेस में विशेष अनुमति मिलने के बाद आ सकते हैं। सरकारी प्रेस में एक बेहद सिक्रेट जगह पर नोट छापने की प्लेट्स रखी होती हैं। प्रेस में इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। कैमरा, बायोमेट्रिक, सुरक्षा गार्ड और अन्य अत्याधुनिक सिक्वोरिटी तकनीक की निगरानी में ये प्लेट्स रखी रहती हैं। जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो एक प्रोटोकॉल के तहत इन्हें गुप्त दराजों से निकाला जाता है। कब कौन सी प्लेट का इस्तेमाल हुआ। कितनी देर ये तिजोरी से बाहर रही, कब इसे फिर से तिजोरी में रखी गई, हर एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। इन करंसी प्लेट्स का एक समय तक इस्तेमाल होता है, फिर इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। ये काम भी एक निश्चित

की थी, लेकिन अब तक वे इस संकट से निपटने के लिए कोई पक्की योजना नहीं बना पाए हैं। वर्ल्ड बैंक के ताज़ा आंकड़े एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं– नेपाल के 82 प्रतिशत कार्यबल का इस्तेमाल अनौपचारिक रूप से किया जाता है, और 2024 में देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी सिर्फ .1,447 थी। लाखों नेपालियों के लिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं – ये उनकी रोज़ की सच्चाई हैं।अभी भी समय है।

यह देखना होगा कि क्या जेन–जेड नेता अपनी मंजूर पार्टियों के बीच कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बना पाते हैं और स्थापित राजनीतिक पार्टियों से लड़ने के लिए अपनी ताकतों को इकट्ठा कर पाते हैं, जिनके पास अच्छी तरह से काम करने वाली चुनावी मशीनरी है ? सिटीजन काउंसिल के कुछ वरीय नेता और साथ ही प्रधानमंत्री सुशीला कार्की भी एक ऐसे रूफ के गठन में दिलचस्पी रखते हैं जो सितंबर के विद्रोह के दौरान उठाई गई मांगों के आधार पर 5 मार्च के चुनाव लड़ेगा। अगर एकता की यह कोशिश सफल होती है, तो जेन–जेड से पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों को कड़ी टक्कर मिलने की कुछ संभावना है।

नियम के तहत होता है। फिल्म में करेंसी प्लेट की चोरी या नकल जितनी आसान दिखाई जाती है, वो असल में नामुमकिन है, क्योंकि, ऐसे प्रेस बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में होते हैं। प्लेट्स की चोरी तो दूर उसके पास भी अगर कोई पहुंच जाए तो पूरे सिस्टम को अलर्ट चला जाता है और जांच शुरू हो जाती है।

यह सही है कि नकली नोटों का कारोबार होता है, लेकिन यह उस तरीके से नहीं होता, जैसा फिल्म में दिखाया गया है। धुरंधर में भारत से जुड़ी तीन बड़ी आतंकी घटनाओं के तार पाकिस्तान से जुड़े होने का सच तो दिखाया गया है, इसमें पहली दो घटनाएं एनडीए शासनकाल में हुई हैं, और तीसरी यूपीए के शासन में हुई है। इसी में सुरक्षा में चूक और मंत्री का भ्रष्टाचार दिखाया गया है, जो जाहिर तौर पर कांग्रेस पर निशाना है। फिल्म के आखिरी में ये नया भारत है घर में घुस कर मारता है, जैसे संवाद का आ जाना पक्के तौर पर मुहर लगा देता है कि धुरंधर भाजपा के प्रचारतंत्र की देन है। दुनिया के हर आतंकी हमले के पीछे इसमें पाकिस्तान का हाथ बताया गया है। अजित डोभाल या अजय सान्याल बने माधवन शुरु से हैरान, परेशान और काफी हद तक कुठित नजर आते हैं कि देश को आतंकी हमलों से बचा नहीं पा रहे। फिल्म का अगला भाग लाने के लिए रणवीर सिंह को जसकीरत सिंह रंगी दिखाया गया है, जिसे जेल से निकालकर अजय सान्याल पाकिस्तान में जासूसी के लिए तैयार करते हैं। इसे अनूटे प्रयोग के तौर पर दिखाया गया है, जबकि कई फिल्मों में ऐसा दिखाया जा चुका है कि किसी कैदी को देश की सेवा के लिए तैयार किया जाता है। फिल्म में आईएसआई के मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) से लेकर चौधरी असलम तक सब बड़े साहब का जिक्र करते हैं, लेकिन ये कौन है शायद इसका पता धुरंधर के अगले भाग में पता चले।



पाकिस्तान से सिरसा पहुंची तीन करोड़ की हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

तरनतारन में पांच पिस्तौल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

सिरसा ३१/१२ (संवाददाता): हरियाणा में सिरसा की सीआईए ऐलनाबाद पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान गांव पनिहारी के बस स्टैंड से एक युवक को 450 ग्राम नौ मिलीग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है । पुलिस अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत तीन करोड़ रुपये के लगभग बता रही है। गिरफ्तार किए गए युवक के खिलाफ थाना सदर

सिरसा में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर किया है । पकड़े गए युवक ने प्रारम्भिक पूछताछ में बताया है कि उक्त हेरोइन अमृतसर के रास्ते पाकिस्तान से लाई गई थी और इसे सिरसा व आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई की जानी थी । इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए सिरसा के पुलिस अधीक्षक डॉ. मयंक गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान गुरप्रीत

सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी गांव जसवाल तहसील डेलो,जिला लुधियाना,पंजाब के रूप मे हुई हैं । उन्होंने बताया कि सीआईए उप निरीक्षक जगदीश चंद्र के नेतृत्व में एक पुलिस टीम सिरसा बरनाला रोड़ पर गांव पनिहारी बस स्टैंड पर नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी । इसी दौरान सरदुलगढ़ पंजाब की तरफ से एक बस आकर

गांव पनिहारी बस स्टैंड पर रुकी। बस में से एक नौजवान युवक अपने हाथ में काले रंग का बैग लिए उतरा और उक्त युवक ने पुलिस की गाड़ी को देखकर अचानक सड़क किनारे तेज-तेज कदमों से चलकर भागने का प्रयास करने लगा। इस बीच वहां मौजूद पुलिस पार्टी ने शक के आधार पर उक्त युवक को काबू कर लिया भागने का कारण पूछा तो युवक कोई संतोषजनक जबाब

नही दे पाया। शक के आधार पर पुलिस पार्टी ने उक्त युवक को काबू कर राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में युवक की तलाशी ली तो उसके कब्जा से करीब तीन करोड़ रुपए की 450 ग्राम 09 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई । उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक के खिलाफ थाना सदर सिरसा में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरु की गई है।

अमृतसर ३१/१२ (संवाददाता): पंजाब में एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने पांच पिस्तौल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने मंगलवार को बताया कि आरोपी की पहचान नौशेरा, तरनतारन निवासी जोधबीर सिंह के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 5 पिस्तौल बरामद की, जिसमें दो पीएक्स पिस्तौल, एक .30 बोर पिस्तौल (स्टार मार्क) और दो 9 मिमी ग्लॉक पिस्तौल शामिल हैं। डीजीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि जोधबीर सिंह एक पाकिस्तान स्थित



ड्रग तस्कर के संपर्क में है, जो अवैध हथियारों की आपूर्ति करता है। इस संबंध में एसएसओसी अमृतसर में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, और अन्य सहयोगियों को पकड़ने और सभी पिछड़े और आगे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

हिमाचल प्रदेश में लू का कहर जारी, भाजपा की गलत नीतियों के कारण किसान दुखी : गर्ग

अगले सप्ताह राहत मिलने के आसार



शिमला ३१/१२ (संवाददाता): हिमाचल प्रदेश में शनिवार और रविवार को तीव्र गर्मी का सामना करना पड़ा, जिसमें ऊना तथा पांवटा साहिब ने इस मौसम का सबसे उच्चतम तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। राज्यभर में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा, पिछले 24 घंटों में कहीं भी वर्षा या हिमपात नहीं हुआ जबकि निम्न पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2—5 डिग्री सेल्सियस कम रहा, मध्य पहाड़ी इलाकों में तापमान सामान्य से 2—6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। केलांग राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। सुंदरनगर (36.5 डिग्री सेल्सियस), कांगड़ा (36.9

डिग्री सेल्सियस) और बिलासपुर (37.5 डिग्री सेल्सियस) जैसे अन्य शहरों में भी असामान्य रूप से उच्च तापमान रहा। कुल्लू के बजोरा और किन्नौर के ताबो में 48 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएँ चलीं।

शिमला मौसम केंद्र ने 30 अप्रैल तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा, एक—तीन मई तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और तेज हवाएं (40—50 किमी प्रति घंटे) चलने के आसार हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान में चक्रीय परिसंचरण के कारण मौसम प्रभावित होना और निम्न क्षेत्र जैसे ऊना, बिलासपुर तथा कांगड़ा में गर्मी बनी रहने का अनुमान है। आने वाले कुछ दिनों तक गर्म और शुष्क मौसम जारी रहने का अनुमान है। सप्ताहांत तक हल्की बारिश और आंधी-तूफान आने के आसार हैं।

चंडीगढ़ ३१/१२ (संवाददाता): हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने राज्यस्तरीय अनाज मण्डी दौरे के दौरान किसान और आढ़तियों से बातचीत करने के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश का किसान एवं आढ़ती बेहद दुखी है। गर्ग ने कहा कि मण्डियों में आज भी 31 लाख टन गेहूं पड़ी हुई है। सरकार की लाहपरवाही के कारण मण्डियां गेहूं से भरी पड़ी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के गेहूं खरीद, उठान और भुगतान 48 घंटे में करने के सभी दावे पूरी तरह से विफल सिद्ध हुए है। उन्होंने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद एक अप्रैल से शुरु की गई। आज 27 दिन बीत जाने के बाद भी गेहूं खरीद का उठान और भुगतान नहीं हो पाया है। गेहूं उठान और भुगतान न होने के कारण किसान और आढ़तियों में सरकार के प्रति बड़ी भारी नाराजगी है। गेहूं खरीद के समय दो बार

बारिश होने के कारण हजारों कि्वंटल गेहूं खराब हो गई है और खेतों में बिजली की तारे नीचे लटकने के कारण हजारों एकड़ फसल जलकर राख हो गई है। जिसके कारण किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को गेहूं खराब होने और फसल जलने के नुकसान की तुरंत भरपाई करनी चाहिए और मण्डियों में तुरंत प्रभाव से गेहूं का उठान और भुगतान किया जाये। श्री गर्ग ने कहा कि सरकार ने गेहूं उठान का टैंडर और मण्डियों में बारदान देर से देने से गेहूं के उठान से देरी हुई है जिसका खिमाजा किसान और आढ़तियों को भुगतान पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार को गेहूं उठान में देरी करने वालों ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मण्डियों में अनाज खरीद करने के लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को मण्डियों में अनाज खरीद के लिए हर प्रकार की व्यवस्था पहले से ही करनी चाहिए।

केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बागवानी परियोजनाओं की समीक्षा की

शिमला ३१/१२ (संवाददाता): हमाचल प्रदेश के शिमला में उप मुख्य सचैतक केवल सिंह पठानिया ने शनिवार को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बागवानी से संबंधित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पठानिया ने कहा कि शाहपुर में शीघ्र ही उद्यान उत्कृष्टता उप केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इस केन्द्र की स्थापना के लिए

इजरायल के विशेषज्ञ दल ने विभाग के अधिाकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया था। इस रिपोर्ट को प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार शीघ्र ही इस केन्द्र की स्थापना का मामला केन्द्र सरकार के साथ उठाएगी।

इस केन्द्र की स्थापना पर पांच करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उप मुख्य सचैतक ने कृषि विभाग के अधिाकारियों को झुलाड़ फार्म

की भूमि उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एचपी शिवा परियोजना की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बागवानी विभाग में रक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा तथा पीसीडीओ शाहपुर में भी पदों का सृजन किया जाएगा। पठानिया ने कहा कि

प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि तथा बागवानी क्षेत्र के विकास को विशेष अधिमान दे रही है।

इस क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी का समावेश किया जा रहा है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सिट्रस प्रजाति के फलों के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इसी के दृष्टिगत विधानसभा क्षेत्र में फलों के उत्पादन के विविधीकरण

के लिए नवोन्मेषी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में लोगों को नवीन प्रौद्योगिकी तथा फसलों और फलों की उन्नत प्रजातियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में निदेशक बागवानी, संयुक्त सचिव बागवानी, परियोजना निदेशक एचपी शिवा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हरियाणा को झटका : पंजाब ने रोका भाखड़ा का पानी, सीएम मान बोले— हमारे पास एक बूंद फालतू नहीं

चण्डीगढ़ ३१/१२ (संवाददाता): पानी के मुद्दे पर एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा आमने-सामने आ गया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हरियाणा की नायब सैनी सरकार को बड़ा झटका देते हुए भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले साढ़े 9 हजार क्यूसिक पानी को घटाकर 4000 क्यूसिक कर दिया है। पंजाब के इस कड़े फैसले से हरियाणा में गर्मी के सीजन में पानी का संकट गहरा सकता है। इस

संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तरफ से पंजाब के खिलाफ गंदी चाल चली जा रही है। जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। मान का कहना है कि भाजपा ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) पर दबाव बनाया जा रहा है कि हरियाणा को उसकी जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाए। पंजाब के पास फालतू पानी नहीं



है जो हर किसी को दिया जाए। जबकि हरियाणा अपने हिस्से का तय पानी पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। ऐसे में पंजाब के पास हरियाणा के

अतिरिक्त पानी नहीं है। सीएम मान ने कहा कि पानी का जो सिस्टम बना हुआ है उसके हिसाब से हर साल 21 मई से अगले वर्ष 21 मई तक पानी का हिसाब रखा जाता है। इस हिसाब से हरियाणा ने पूरे साल का अपने हिस्से का पानी मार्च में ही इस्तेमाल कर लिया है। हालांकि इससे पहले कभी भी पानी का हिसाब नहीं रखा गया। क्योंकि पूर्व सरकारों की मिलीभगत से पानी का खेल चलता रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप

सरकार पानी की बूंद-बूंद का हिसाब रख रही है। सीएम मान ने कहा कि हम अपने हिस्से का पानी नहीं दे सकते। इसलिए भाजपा बीबीएमबी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। पंजाब के पास एक बूंद भी फालतू नहीं है। हालांकि मानवता के आ्ार पर हरियाणा को 4000 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है। क्योंकि पानी सभी की जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा पानी हरियाणा को नहीं दिया जा सकता।



धर्मेन्द्र प्रधान ने 'स्वच्छ, सुंदर, सबुजा अंगुल' अभियान में भाग लिया

अंगुल ३१/१२ (संवाददाता): केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने ओडिशा के अंगुल में %स्वच्छ, सुंदर, सबुजा अंगुल% स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने अंगुल नगर पालिका, अंगुल में 27 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसी बीच, ओडिशा से एक अन्य घटनाक्रम में, केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने शनिवार को राउरकेला स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) में एक खेल परिसर का उद्घाटन किया और विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

प्रधान ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)



की इंजीनियरिंग श्रेणी में एनआईटी राउरकेला को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वे संस्थान को बधाई देने और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए परिसर में आए थे। प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तकनीकी परिवर्तन के कगार पर है और

कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना 2036 तक ओडिशा के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनआईटी राउरकेला इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस वर्ष की एनआईआरएफ (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क)

रैंकिंग में, एनआईटी राउरकेला ने इंजीनियरिंग कॉलेज श्रेणी में 13वां स्थान प्राप्त किया है। मैं उन्हें बधाई देने और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए एनआईटी राउरकेला परिसर में आया था, उन्होंने कहा। प्रधान ने आगे कहा, आने वाले दिनों में देश में एक तकनीकी क्रांति होने वाली है, और प्रधानमंत्री मोदी ने एक विकसित भारत के निर्माण का आह्वान किया है।

ओडिशा 2036 तक एक विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एनआईटी राउरकेला इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। इससे पहले गुरुवार को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर

रायराखोल में 250 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

इस अवसर पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, हमने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर शुशासन दिवस मनाया। आज यहां लगभग 250 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का अनावरण किया गया।

इससे पहले, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने चंदाका में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) के लिए एक नए प्रशिक्षण एवं ब्रीफिंग केंद्र का उद्घाटन किया, जहां एक समय में 400 जवानों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। उन्होंने उसी स्थान पर एक आधुनिक आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया।

राउरकेला इस्पात संयंत्र ने सेल टेबल टेनिस चैंपियनशिप-2025 जीती



राउरकेला ३१/१२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) ने इस्पात इंडोर स्टेडियम में बहुत उत्साह और और कड़े प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के बीच संपन्न हुई सेल टेबल टेनिस चैंपियनशिप-2025 की पुरुष वर्ग में चैंपियन का खिताब जीता। आरएसपी टीम ने फाइनल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी) को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। आरएसपी महिला टीम भी चैंपियनशिप में उप-विजेता रही, फाइनल में उसे डीएसपी महिला टीम से हार का सामना करना पड़ा। कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), आरएसपी, श्री अनिल कुमार, समापन पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने विजेताओं और उपविजेताओं को

सज्जानित किया। मुख्य महाप्रबंधक (नगर-सेवाएं एवं सीएसआर), श्री टी जी कानेकर संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस अवसर पर उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री अनिल कुमार ने अनुशासन, टीमवर्क तथा स्वस्थ कार्य संस्कृति के विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न सेल इकाइयों की टीमों की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर-इकाई सौहार्द एवं संगठनात्मक जुड़ाव को मजबूती मिलती है।

आरएसपी पुरुष टीम में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा), डॉ. संजय तिवारी, अनुभाग अधिकारी

(विज्ञ एवं लेखा), श्री राजेश चौरसिया एवं कनिष्ठ अभियंता (सामग्री प्रबंधन विभाग-भण्डारण), श्री अल्बर्ट किंडो शामिल थे।

उल्लेखनीय है कि सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली टीमों में सेल निगमित कार्यालय, आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र (आईएसपी), राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी) शामिल थीं। इस चैंपियनशिप का स्थानीय स्तर पर सफल समन्वय उप प्रबंधक (क्रीडा), आरएसपी, श्री रघु नंदन पाढ़ी, द्वारा किया गया। प्रतियोगिता ने सेल की विभिन्न इकाइयों के बीच खेल प्रतिभा, टीम भावना एवं सौहार्द का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

गांव में भालू की हलचल से दहशत फैल गई

नुआपाड़ा ३१/१२ (संवाददाता): जिले में सिनापाली पुलिस स्टेशन के तहत गंडाबाहली गांव में देर रात भालू घुस रहे हैं, वे झुंड में घूम रहे हैं और गांव की सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे निवासियों में व्यापक डर फैल गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, देर रात तीन भालूओं को गांव में घूमते देखा गया, जिससे स्थानीय लोगों को शाम के बाद बाहर निकलने से रोकना पड़ा। बताया जाता है कि बार-बार भालूओं के दिखने से गांव में दहशत फैल गई है, जिससे निवासी शाम और रात में अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले कई दिनों से इसानी बस्तियों में भालूओं की मौजूदगी ने रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। सुरक्षा चिंताओं के कारण लोग कथित तौर पर केवल सुबह के समय ही बाहर निकल रहे हैं।

भालू के हमले के बाद महिला की मौत' पिछले शुक्रवार को भालू के हमले में एक महिला की कथित मौत के बाद तनाव और बढ़ गया।



रिपोर्ट्स के अनुसार, एक भालू के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। बाद में नुआपाड़ा जिला मुख्यालय अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से ग्रामीणों, खासकर महिलाओं और बुजुर्ग निवासियों में चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोग तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं निवासियों ने वन विभाग से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। बताया जाता है कि कुछ वन विभाग के कर्मियों को गांव में तैनात किया गया है और वे भालूओं की गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण भीष्मराज मेहर ने कहा, पिछले 10 से 15 दिनों से गांव और उसके

आसपास भालू देखे जा रहे हैं। हम पूरी तरह से डरे हुए हैं। वे इसानी बस्तियों में घुस रहे हैं और घरों के करीब भी आ रहे हैं। हाल ही में एक महिला पर भालू ने हमला किया और उसकी जान चली गई। अगर सरकार ने पहले कार्रवाई की होती और हमारी सुरक्षा पर ध्यान दिया होता, तो स्थिति अलग हो सकती थी। एक अन्य ग्रामीण सुरेखा मेहर ने कहा, डर के मोरे हम केवल सुबह के समय ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के समर्थन का स्वागत करते हैं। सूत्रों के अनुसार, स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है क्योंकि ग्रामीण वन विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं।

15 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई की जाएगी



जयोंझर ३१/१२ (संवाददाता): मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को घोषणा की कि अगले तीन सालों में राज्य में 15 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई की जाएगी। पालासापंगा लैन्ड्स में 2025-26 खरीफ सीज़न के लिए जयोंझर ज़िले में धान खरीद प्रक्रिया शुरू करते हुए, माझी ने कहा कि पिछले साल, लगभग 20 लाख किसानों को 7,000 करोड़ रुपये की इनपुट सहायता मिली थी। इस साल, यह संज्या और बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार धान पर 800 रुपये प्रति क्विंटल का बोनास दे रही है, जिससे किसानों का खेती के प्रति मनोबल बढ़ा है। सरकार धान के साथ-साथ गैर-धान फसलों में भी किसानों को और प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। किसानों को सिर्फ धान ही नहीं, बल्कि दालें, तिलहन और मोटे अनाज भी उगाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 10 जनवरी तक सभी जिलों में धान की खरीद शुरू हो जाएगी। सभी अधिकारियों को पूरी धान खरीद प्रक्रिया को

पारदर्शी तरीके से करने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा। धान की कटाई और संबंधित क्षेत्रों में सहकारी निकायों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, माझी ने कहा कि राज्य में 1,542 नए PACS और LAMPS स्थापित किए गए हैं। सरकार इन सोसाइटियों को चालू करने के लिए 5 लाख रुपये की सौड मनी भी दे रही है। वर्तमान में, राज्य में 4,253 PACS और LAMPS हैं। इन्हें वन-स्टॉप सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, उन्होंने कहा।

नए साल के लिए आधी रात को पुरी जगन्नाथ मंदिर खोलना 'गैर-सनातनी' है-मंदिर मैनेजिंग कमिटी सदस्य

भुवनेश्वर ३१/१२ (संवाददाता): हिंदू संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध धार्मिक संस्थाओं और नेताओं के बीच बढ़ते गुस्से के बीच, श्री जगन्नाथ मंदिर मैनेजिंग कमिटी के एक सदस्य ने अधिकारियों से अपील की है कि वे अंग्रेजी नए साल के मौके पर आधी रात को श्रीमंदिर न खोलें। मैनेजिंग कमिटी ने 'गैर-सनातनी' रिवाज पर सवाल उठाया, स्ट्रुञ्ज और ओडिशा सरकार को लिखा श्री जगन्नाथ मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन और ओडिशा सरकार को लिखे एक लेटर में, मैनेजिंग कमिटी के सदस्य महेश कुमार साहू ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को मंदिर खुला रखने के रिवाज को गैर-सनातनी और धार्मिक रूप से गलत बताया। कमिटी सदस्य ने कहा, 'सनातन परंपराओं के खिलाफ' साहू ने कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ सनातनी हिंदुओं के आराध्य देवता हैं और मंदिर में सभी रस्में पवित्र सनातन ग्रंथों के अनुसार सज्जी से की जाती हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि हाल के सालों में, 1

जनवरी को आधी रात को मंदिर खोलना एक रेगुलर रिवाज बन गया है, जो उनके अनुसार, स्थापित धार्मिक नियमों के खिलाफ है। उन्होंने आगे बताया कि इस रिवाज पर धार्मिक नेताओं और संगठनों ने लगातार आपत्ति जताई है, जो हर साल अपना गुस्सा जाहिर करते रहे हैं। इस मुद्दे को धार्मिक रूप से सेंसिटिव बताते हुए, साहू ने स्ट्रुञ्ज के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अरबिंद पाथी और ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन से अपील की कि वे यह पक्का करें कि श्रीमंदिर में देवताओं के रोजाना के रीति-रिवाज पारंपरिक तरीके से किए जाएं, और इंग्लिश न्यू ईयर के लिए रात में देवताओं को जगाया न जाए। यह अपील हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक में धार्मिक परंपराओं और बदलते तरीकों के बीच चल रही बहस को दिखाती है।

इस्पात जनरल हस्पताल में अग्नाशयशोथ के एक अति गंभीर मामले का सफल इलाज

राउरकेला ३१/१२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के इस्पात जनरल हस्पताल (आईजीएच) के चिकित्सकों ने गंभीर रूप से अग्नाशयशोथ से पीड़ित मरीज का सफलतापूर्वक उपचार किया जिसकी बीमारी शराब प्रत्याहार के कारण बुरी तरह से प्रभावित थी।

मरीज अत्यंत गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जिसके लिए तत्काल चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। वरिष्ठ विशेषज्ञ परामर्शदाता एवं पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा), डॉ. पी के महापात्रा एवं तथा वरिष्ठ परामर्शदाता (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा), डॉ. मोनालिसा महंती ने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी टीम की नेतृत्व की और शीघ्र ही गंभीर अग्नाशयशोथ का पता लगाया तथा और प्रभावी उपचार रणनीतियों को लागू किया।

इस बीच, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा)



और प्रभारी (सीसीयू) डॉ. संजुका पाणिग्राही और वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा), डॉ. पी जे रॉय के नेतृत्व में क्रिटिकल केयर टीम ने मरीज की स्थिति को स्थिर करने के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों सहित चौबीसों घंटे गहन देखभाल प्रदान की। इस सफलता में आईसीयू नर्सिंग टीम का बेजोड़ प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण तत्व था। वरिष्ठ

नर्सिंग सिस्टर, शाइनी जॉर्ज और नर्सिंग सिस्टर अनीता जेना के नेतृत्व में, नर्सों ने उत्कृष्ट सतर्कता, नैदानिक विशेषज्ञता और संवेदनशील रोगी सेवा का प्रदर्शन किया, जो रोगी की स्थिति में सुधार लाने और स्वस्थ को बहाल करने में निर्णायक साबित हुआ। चिकित्सकीय स्थिति में सुधार के पश्चात मरीज को आईजीएच के मानसिक स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक सुव्यवस्थित नशामुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रम

में शामिल किया जाएगा, ताकि दीर्घकालिक एवं समग्र सहयोग सुनिश्चित किया जा सके।

यह मामला जटिल चिकित्सकीय आपात स्थितियों से निपटने में आईजीएच की उत्कृष्टता, समन्वित टीमवर्क, नर्सिंग नेतृत्व एवं समग्र चिकित्सा सेवा दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। अस्पताल सभी हितधारकों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।